www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 1 जुलाई 2019

दैनिक जागरण
आत्ममुग्धता पतन की पहली सीढ़ी है

कश्मीर में रोका जाए पाकिस्तान का दखल

विवेक काटजू

भारत की ढुलमुल नीति से पाकिस्तान ने कश्मीर में इतनी पैठ बना ली है कि वहां हुर्रियत से लेकर मुख्यधारा के दल भी वार्ता में पाक को पक्ष बनाने की मांग करते हैं। अब पुरानी गलती सुधारनी होगी

बीते कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा फिर सुर्खियों में आया है। इसकी शुरुआत राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हुर्रियत नेता बातचीत के लिए तैयार नहीं। उनके बयान के तुरंत बाद हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि उनका समूह हमेशा सार्थक वार्ता के लिए तैयार रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अतीत में भी हुर्रियत भारत और पाकिस्तान के साथ सक्रिय रही है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में जब शंघाई सहयोग सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिश्केक जा रहे थे तो उससे पहले फारूक ने कहा था मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को एक दूसरे के साथ सक्रियता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 'कश्मीर में आगे बढ़ने और दर्दनाक खूनखराबे के दौर को खत्म करने के लिए राजनीतिक सक्रियता ही सबसे प्रभावी तरीका है।' मलिक और मीरवाइज के बयानों के बाद भाजपा के एक नेता ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं जो भारतीय संविधान में आस्था रखते हों। भाजपा की राज्य इकाई ने और कड़ा रुख अपनाते हुए हुर्रियत से पूछा कि क्या वह सार्वजनिक रूप से जम्मू-कश्मीर को गैर-विवादित क्षेत्र मानते हुए उसे भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देगी। यह एक अहम शर्त है, क्योंकि राज्य की स्थिति को विवादित मानने में हुर्रियत पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाती है।

ऐसे में हम जम्मू-कश्मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से उम्मीद कर सकते हैं कि वे वार्ता के मुद्दे पर अपना पुराना रुख दोहराएंगे। पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस दोनों ने वार्ता की मांग की और कहा कि सभी पक्षों के बीच वार्ता के माध्यम से ही जम्मू-कश्मीर के मुद्दे का समाधान निकल सकता है। नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भारत-पाकिस्तान के बीच वार्ता शुरू होने की इच्छा दोहराई। ऐसा करते हुए उमर अब्दुल्ला इस मसले पर राज्य में मुख्यधारा के दलों का रुख ही जाहिर कर रहे थे।

इस मसले पर सभी पक्षों की ओर से हुई बयानबाजी के कुछ दिन बाद बतौर गृहमंत्री अमित शाह ने अपना पहला जम्मू-कश्मीर दौरा किया। उन्होंने कई आला अधिकारियों के साथ बातचीत की। इनमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने से लेकर विकास गतिविधियों का काम देख रहे अधिकारी शामिल थे। शाह ने उनसे अलग-अलग बातचीत की। सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर उनका दो-टूक संदेश था कि आतंक और आतंकियों के साथ बिल्कुल नरमी न बरती जाए। आतंक को मिलने वाली वित्तीय मदद पर भी पूरी नकेल कसी जाए। शाह ने कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने पर जोर देने की बात कही। अपने रुख को लेकर जनता में संदेश देने के लिए शाह इंस्पेक्टर अरशद खान के घर भी गए। अरशद खान ने अनंतनाग में आतंकियों से संघर्ष करते हुए असाधारण साहस का परिचय दिया था। शाह ने कहा कि उनकी शहादत हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कश्मीर घाटी में रहने वाले गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों से बातचीत की। शाह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि तमाम अन्य राज्यों में सिरे चढ़ चुकीं विकास की कई योजनाएं जम्मू-कश्मीर में भी तेज रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए।

स्पष्ट है कि गृह मंत्री ने हुर्रियत से बातचीत की कोई मंशा नहीं दिखाई। इससे उन अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के हालात संभालने में अपनी नीति बदलने जा रही है। खासतौर से सत्यपाल मलिक द्वारा हुर्रियत को लेकर दिए बयान से कुछ गफलत अवश्य पैदा हो गई थी। आखिर मलिक ने यह क्यों किया? क्या वह केवल हुर्रियत नेताओं के बयान पर ही प्रतिक्रिया दे रहे थे? तथ्य यही है कि कोई भी सरकार देश में तमाम चैनलों के माध्यम से विभिन्न समूहों के संपर्क में होती है। कुछ मामलों में खुफिया एजेंसियां भी इनमें शामिल होती हैं। इसमें कुछ गलत नहीं। क्या कुछ चैनलों के माध्यम से हुर्रियत को कोई संदेश दिया गया जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं?

बहरहाल मलिक के बयान के बाद मीरवाइज उमर फारूक और राज्य में मुख्यधारा के दलों द्वारा वार्ता में पाकिस्तान को पक्ष बनाने का क्या निहितार्थ है? यह एक और मिसाल है कि राज्य के मामलों में पाकिस्तान कैसे अपनी पैठ बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि सरकारों का रवैया ढुलमुल रहा और राज्य से जुड़े बुनियादी सिद्धांतों को लेकर अतीत में सरकारें भ्रम का शिकार रहीं। सरकार की इन नीतियों से ही राज्य के मसलों का समाधान और पाकिस्तान की काट होनी चाहिए थी। मगर अफसोस की बात कि पिछली सरकारों ने इसकी अनदेखी की।

भले ही भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल हो, लेकिन यह भारतीय संघ का अभिन्न अंग है। इस तथ्य को देखते हुए राज्य के शासन-संचालन या राज्य के केंद्र से संबंधों को लेकर किसी भी अन्य देश को कभी भी पक्ष नहीं बनाया जा सकता। ये मुद्दे भारत के आंतरिक मामलों के दायरे में ही आते हैं। राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। शिमला समझौते के तहत भारत इस मुद्दे को शांतिपूर्वक और बातचीत के जरिये सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही इस मुद्दे का बाहरी पहलू है और यहीं पाकिस्तान दाखिल होता है। इस या किसी अन्य मुद्दे को लेकर द्विपक्षीय बातचीत तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान आतंक की अपनी नीति नहीं छोड़ देता।

वास्तव में होना यही चाहिए था कि भारत ऐसी स्थितियां बनने ही नहीं देता जिसमें पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर में इतनी पैठ बनाने की गुंजाइश मिल जाती। पाकिस्तानी हस्तक्षेप को रोकने के लिए भारत को हरसंभव प्रयास करने चाहिए थे। इसके लिए चाहे विचारधारा का सहारा लिया जाता या जम्मू-कश्मीर के लोगों को हथियारबंद प्रशिक्षण देने से लेकर घुसपैठिये भेजना या राज्य के लोगों में पाकिस्तानी खौफ पैदा करना कि उससे उन्हें कितना नुकसान पहुंच सकता है। मगर भारत यह सब करने में नाकाम रहा। यह एक कड़वी और तल्ख अनुभूति जरूर है, लेकिन यही सच है। अब यह जरूरी हो गया कि पाकिस्तान को प्रभावी बनाने वाले पहलुओं को निष्प्रभावी किया जाए। इसे संभव बनाए बिना कोई भी सरकार कश्मीर में सौहार्द कायम नहीं कर सकती। बेहतर शासन से लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में सुधार एक सही मकसद है और इससे जनसामान्य में लोकप्रियता अवश्य बढ़ेगी, लेकिन केवल यही कश्मीर घाटी में स्थायी शांति और स्थायित्व लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आतंक का रास्ता पकड़ने वाले सरकार से सख्ती की ही उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले युवाओं पर अंकुश लगाया जाए। पाकिस्तान से निपटने में यह प्रभावी उपाय साबित होगा। भारत को मुख्य रूप से इसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

जल संरक्षण का आंदोलन

प्रधानमंत्री ने दूसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के बाद अपने पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिये बिल्कुल सही समय पर यह कहा कि जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। जल संरक्षण के लिए उन्होंने हर किसी से आगे आने का आग्रह भी किया। इस आग्रह पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि अपने देश में साल भर में वर्षा से जो जल प्राप्त होता है उसका केवल आठ प्रतिशत ही संरक्षित हो पाता है। एक ऐसे समय जब पानी की कमी से प्रभावित होने वाले इलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है तब इसके अलावा और कोई राह नहीं कि पानी बचाने और उसे संरक्षित करने के हरसंभव उपाय किए जाएं। प्रधानमंत्री ने यह उम्मीद जताई कि देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से मौजूदा जल संकट का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन यह आसान काम नहीं और इसलिए नहीं, क्योंकि जल संरक्षण के तौर-तरीकों को अमल में लाने के मामले में सरकारी तंत्र की भूमिका काफी निराशाजनक है। इससे इन्कार नहीं कि विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण संबंधी नियम-कानून बना रखे हैं, लेकिन देखने में यही आता है कि वे कागजों तक ही अधिक सीमित हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सरकारी अमला आमतौर पर बारिश के समय ही सक्रिय होता है और दिखावटी खानापूरी करके कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। सरकारी तंत्र की ढिलाई के कारण देश के एक बड़े हिस्से में आम जनता चाह कर भी जल संरक्षण के काम में हिस्सेदार नहीं बन पाती। परिणाम यह होता है कि बारिश का अधिकांश जल व्यर्थ चला जाता है।

यह समय की मांग है कि केंद्र सरकार जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए न केवल खुद सक्रिय हो, बल्कि राज्य सरकारों के साथ-साथ उनकी विभिन्न एजेंसियों को भी सक्रिय करे। यह सक्रियता सतत नजर आनी चाहिए ताकि न केवल बारिश के जल का संरक्षण हो सके, बल्कि पानी की बर्बादी को भी रोका जा सके। यह ठीक नहीं कि जब जल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है तब पानी की बर्बादी को रोकने और उसे दूषित होने से बचाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब भूमिगत जल के अनावश्यक दोहन पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है तब यह देखने में आ रहा है कि ऐसा करने से बचा जा रहा है। एक समस्या यह भी है कि विभिन्न जल स्रोतों की सही तरह से देखभाल भी नहीं हो रही है। परंपरागत जल स्रोतों को बचाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वह कुछ ही स्थानों पर जैसे-तैसे आगे बढ़ता दिख रहा है। निःसंदेह इसकी वजह भी सरकारी तंत्र की शिथिलता ही है। यदि जल संरक्षण के कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाना है तो यह सुनिश्चित करना ही होगा कि बारिश के जल को संरक्षित करने, पानी के दुरुपयोग को रोकने और उसे प्रदूषित होने से बचाने की जो योजनाएं जिस विभाग के तहत आती हैं वे अपना काम मुस्तैदी से करें। यह तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब इन विभागों को जवाबदेह बनाने के साथ ही उनके कामकाज की सतत निगरानी भी की जाएगी।

सड़क सुरक्षा

उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर आखिरकार अब कुछ गंभीरता नजर आ रही है। लीड एजेंसी का अधिकारिक रूप से गठन कर इसकी कमान संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी के हाथों में देने के फैसले से सड़क सुरक्षा के कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह सारी कवायद सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद हुई है। इससे साफ है कि शुरुआत में सड़क सुरक्षा के कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया गया। देखा जाए तो प्रदेश में सड़क सुरक्षा की जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही है। चारधाम यात्रा एवं पर्यटन सीजन के दौरान प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं के ग्राफ को लेकर सरकार एवं शासन स्तर पर कई मर्तबा बैठकें तो हुईं, लेकिन इनमें कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सभी राज्यों में सड़क सुरक्षा परिषद गठित करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत राज्य स्तर और जिला स्तर पर समितियों का गठन करना था। राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे तो जिला स्तर पर इनकी कमान जिलाधिकारियों को सौंपी गई। इनका मकसद सड़क सुरक्षा को लेकर योजनाएं बनाना और अभी तक हुए कार्यों पर निगरानी रखना है। कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए एक संयुक्त एजेंसी बनाने को कहा गया, जिसे सड़क सुरक्षा कार्यों की लीड एजेंसी का नाम दिया गया। इसकी कमान परिवहन आयुक्त को सौंपी गई। इस समिति का कार्य सड़कों का सर्वे कर इनकी समस्याओं को इंगित करना और संबंधित विभाग के समन्वय से इन समस्याओं का निस्तारण करना है। यह समिति नाम के लिए तो काफी पहले अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन इसमें गंभीरता से काम नहीं हो पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और समिति की कमान परिवहन आयुक्त से हटाकर पूर्णकालिक रूप से अन्य विभागीय अधिकारी को सौंपने को कहा। इस कड़ी में अब संयुक्त आयुक्त को इस समिति की कमान सौंपी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह लीड एजेंसी अपनी सार्थकता को सिद्ध करते हुए सड़क सुरक्षा के कार्यों को गति देगी। सरकार को भी चाहिए कि वह इस समिति को क्रियाशील करे और पर्याप्त बजट देकर सड़क सुरक्षा के कार्यों को धरातल पर उतारे।

चुनौतियों से जूझता चिकित्सा जगत

डॉ. सूर्यकांत

जीवन या मृत्यु चिकित्सक नहीं, ईश्वर के हाथ में है, इस बात का ध्यान समाज को सदैव रखना चाहिए

पश्चिम बंगाल की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले महान चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी डॉ. बीसी रॉय के जन्म दिवस एक जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉ. रॉय ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन इसी बंगाल में चिकित्सकों को हिंसा का शिकार होना पड़ेगा। इसके विरोध में उन्हें करीब एक सप्ताह तक आंदोलित होना पड़ेगा और एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी करनी पड़ेगी। यह दुर्योग ही है कि हिंसा का शिकार वह एनआरसी अस्पताल बना जहां डॉ. बीसी रॉय ने चिकित्सा शिक्षक के रूप में कार्य किया था। डॉ. बीसी रॉय बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। उस दौरान भी वह निःशुल्क इलाज किया करते थे। एक समय था जब मरीज और उसके परिजन डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते थे, लेकिन आज वह श्रद्धा, सम्मान और उससे भी बड़ी बात वह अटूट भरोसा कहीं चला गया। अगर हम गहराई में जाकर देखें तो यह परिवर्तन व्यक्ति-व्यक्ति के रूप में दिखता है। इसके साथ ही सामाजिक, व्यावसायिक अंतरसंबंधों के बदलते स्वरूप में भी शिक्षा के आधुनिकीकरण और भूमंडलीकरण ने समाज को नए रूप में ढाला है। चिकित्सा सेवा भी अब सेवा नहीं रही, सर्विस हो गई है, प्रोफेशनल सर्विस, जिसमें तकनीकी दक्षता और कौशल तो बढ़ा है, लेकिन नैतिक दायित्वबोध और गरिमा निश्चित तौर पर अपने पुराने रूप से बदतर हो गई है। इन सब पर व्यावसायिकता हावी हो चुकी है।

पहले चुनिंदा डॉक्टर दूर-दूर तक अपने नाम और कुशलता के लिए जाने जाते थे, परंतु अब डॉक्टर नहीं कारपोरेट, अस्पतालों, विशेषज्ञता और सुपर-स्पेशलाइजेशन का दौर है। अब समाज डॉक्टरों को ईश्वर के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे लगता है कि अधिकांश चिकित्सक येन केन प्रकारेण इलाज के दौरान धन के दोहन में लगे रहते हैं। दवा, सर्जरी और जांचें सब में उसे कमाई के अनैतिक स्रोत दिखते हैं। संदेह का चश्मा हमेशा ही मरीज की आंखों पर रहता है। सबको एक ही नजर से देखने की इस बदली सामाजिक प्रवृत्ति ने मरीज और चिकित्सकों के बीच सदियों से स्थापित श्रद्धा और विश्वास की नींव को जड़ से हिलाकर रख दिया है। पुराने समय में मरीजों और परिजनों का यह भरोसा डॉक्टरों को नैतिक दायित्वबोध और उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक आत्मबल प्रदान करता था जो कि उसके काम की सबसे बड़ी जरूरत थी और बेशक आज भी है।

निजीकरण और व्यावसायीकरण के इस युग में पूंजी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। इसके फायदे कम

हुए हैं, नुकसान अधिक। पूंजी बढ़ने से तकनीकी और आधारभूत ढांचे में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। गांवों और कस्बों में पेड़ों के नीचे खाट और बदहाल अस्पतालों में इलाज के दौर से निकलकर अब स्थिति सेवन स्टार होटलनुमा अस्पतालों तक आ पहुंची है। इससे जहां एक ओर इलाज की गुणवत्ता बढ़ी है तो वहीं खर्चे भी बढ़े हैं। इन बेतहाशा बढ़े खर्चों का अर्थशास्त्र भी डॉक्टरों से मरीजों के संबंधों का मनोविज्ञान और मानसिकता बदल रहा है। जब मरीज की हालत गंभीर हो और धैर्य की सबसे अधिक जरूरत हो तब मरीजों तथा चिकित्सकों के बीच स्थापित मर्यादा एवं अच्छे व्यवहार की लक्ष्मण रेखा अक्सर ही ध्वस्त हो जाती है। कारणों की तह में जाएं तो एक तथ्य यह भी सामने आता है कि दस-दस साल चिकित्साशास्त्र के हर गूढ़ और गहन तथ्यों को समझने-बूझने में लगे डॉक्टरों को मरीजों से उचित तरह से संवाद करने के लिए बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं किया जाता।

एक बड़ा कारण जो डॉक्टर-रोगी के रिश्तों को प्रभावित करता है, वह है डॉक्टरों की कमी। 2018 की नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 11,082 जनसंख्या पर एक एलोपैथिक चिकित्सक है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक (1,000 जनसंख्या पर एक चिकित्सक) से 10 गुना कम है। डॉक्टरों की यह कमी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में और भी ज्यादा है। हाल ही में प्रकाशित स्वास्थ्य मानकों की रिपोर्ट भी यही दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार काफी नीचे हैं। काम के बोझ से जुड़े तनाव तो इस सेवा का हिस्सा बन ही चुके हैं। इन दोनों छोरों पर भी बड़े सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

एक अन्य कारण जो चिकित्सक रोगी के संबंधों को बिगाड़ रहा है, वह है समाज में बढ़ती उग्रता। आज रोगी के परिजनों को लगता है कि सिफारिश कराकर रोगी का अच्छा उपचार कराया जा सकता है। जैसा कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में लोग आए दिन करते रहते हैं। इस सोच के कारण चिकित्सक रोगी का उपचार करे या समाज के बढ़ते उग्र स्वरूप से स्वयं की रक्षा करे या अपने क्लीनिक या अस्पताल के शीशे टूटने से बचाए। यह भी एक विकराल समस्या कुछ वर्षों से बड़ी तेजी से उभरी है। किसी रोगी की यदि उपचार के दौरान मृत्यु हो जाए तो तुरंत आरोप लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मृत्यु हो गई, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी चिकित्सक क्यों चाहेगा कि उसके मरीज की मृत्यु हो जाए या वह ठीक न हो। प्रत्येक चिकित्सक अपने ज्ञान एवं जानकारी से रोगी को ठीक करने की कोशिश करता है, जीवन या मृत्यु चिकित्सक के वश में नहीं, अपितु ईश्वर के हाथ में है, इस बात का ध्यान समाज को सदैव रखना चाहिए। अतः मरीजों और उनके परिजनों को भी अपने रवैये में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। डॉक्टरों से उनके रिश्ते पूरी तरह से व्यावसायिक हों, फिर भी उसमें आत्मीयता, मानवीयता और परस्पर सम्मान का होना नितांत आवश्यक है। भारतीय चिकित्साशास्त्र के महान मनीषी चरक ने क्या खूब कहा था कि मरीज चिकित्सक को चिकित्सा सेवा या परामर्श के बदले धन दे सकता है। धन न हो तो कोई उपहार दे सकता है। यह भी न हो सके तो वह उसके कौशल का प्रचार कर उसके उपकार से निवृत्त हो सकता है। अगर कोई मरीज ऐसा करने में भी अक्षम हो तो वह ईश्वर से उस चिकित्सक के कल्याण की प्रार्थना करे। इस भाव और मानसिकता का मूल चिकित्सक और रोगी, दोनों को समझना होगा, क्योंकि उनका आपसी रिश्ता और सम्मान की भावना इस पुनीत तथा महान चिकित्सा व्यवस्था की नींव है। और इस व्यवस्था पर करोड़ों मरीजों की सेहत तथा जिंदगी टिकी है।

(लेखक लखनऊ स्थित केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

नैतिक मूल्य

वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का पतन तेजी से हो रहा है। लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था का अभाव बढ़ता जा रहा है। अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। इस सामाजिक समस्या के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला यही कि लोगों में चरित्रहीनता बढ़ी है। दूसरा, नैतिकता घटी है। तीसरा, ईश्वर के प्रति विश्वास घटा है। इन बिंदुओं पर विचार करने पर यह निहितार्थ निकलता है कि मानो चरित्र शब्द कुछ समय बाद शब्दकोश का ही विषय होगा। समाज में कोई विरला चरित्रवान दिखाई देगा, जिसे आदर्श माना जा सके। संस्कारों के अभाव में नैतिकता का स्तर गिरना स्वाभाविक है, जबकि नीति से गिरा हुआ समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। आज के दिखावे के युग में आयोजन तो बहुत हो रहे हैं, किंतु उनके मानवीय सरोकार नहीं हैं। इसीलिए इन आयोजनों से कोई सामूहिक हित नहीं होता। अध्यात्म के बिना भौतिक उत्थान का कोई महत्व नहीं है। हृदय निर्मल नहीं है तो सुगंध कहां से आएगी? इसीलिए हृदय की पावनता को विशेष महत्व दिया गया है। मन की पवित्रता के बिना तन की पवित्रता संभव नहीं है। हृदय के पवित्र भाव ही बाह्य रूप में भक्ति, सरलता और आचरण के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस आचरण के अभाव में सर्वत्र अराजकता दिखाई देती है। जीवन से सुख शांति और सरलता मानो विदा हो चुकी है। ऐसे में परमात्मा का आधार ही सुख एवं आनंद प्राप्ति का कारण है। इस संदर्भ में गुरुनानक की वाणी अत्यंत सार्थक है-'नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो एक अधार।'

परमात्मा की अनुभूति हमारे कल्याण का कारण है। इसलिए जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए मानवीय नैतिक मूल्यों पर अमल करना चाहिए। अनेक उदाहरण हैं, जिनसे आस्था, नीति, चरित्र, भक्ति और अध्यात्म की महिमा प्रमाणित हो जाती है। पांडवों की जीत नीतिमार्ग की जीत है। तमाम संकटों के बावजूद वे विजयश्री प्राप्त करने में सफल रहे। शिवाजी और राणाप्रताप के चरित्र हमारी धरोहर हैं। वे न केवल वीरता के प्रतीक थे, बल्कि न्याय और नीति के अनुयायी थे। शत्रु तक उनके चरित्र और व्यवहार के कायल थे। ध्रुव और प्रह्लाद ईश्वर भक्ति के उदाहरण हैं। ईश्वर के प्रति आस्था के बल पर ही उन्होंने मनुष्यमात्र की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

विजय नारायण गुप्त

सीवर सफाई में हो रोबोट का इस्तेमाल

ावीन जैन

देशभर में हर वर्ष करीब 22,000 मजदूर सीवर की सफाई के दौरान मौत के मुंह में समा जाते हैं

हाल ही में कानपुर से खबर आई थी कि सीवर टैंक की सफाई के दौरान दो सफाईकर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उधर मथुरा में भी सीवर की जहरीली गैस से चार लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। कभी नोएडा तो कभी वाराणसी तो कभी दिल्ली तो कभी बड़ौदा से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। बता दें कि देशभर में हर वर्ष करीब 22,000 मजदूर सीवर सफाई के दौरान असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। सीवर में सफाई के लिए उतरने वाले कर्मचारी जहरीली गैस का शिकार हो जाते हैं। जानकारों का कहना है कि सीवर के अंदर मिथेन एवं हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है।
इससे सीव
समय बाद
गौरतल
सुरक्षा मा-
बेल्ट का
हेलमेट, ब
एवं टॉर्च
लेकिन दु

जिन लोगों की मृत्यु हो गई वे इन सब उपकरणों से वंचित थे। उधर बड़ौदा में भी लगभग ऐसा ही हुआ। जिस होटल में सात लोग सीवर सफाई के दौरान मारे गए उनके पास सुरक्षा के पर्याप्त साधन नहीं थे। अब समय आ गया है जब देश में सीवर की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि कानपुर तथा केरल में ऐसी एक नई पद्धति की शुरुआत हुई है। इसमें रोबोट का इस्तेमाल होता
इससे वहां सीवर सफाई में बहुत सहायता
ली है। इस आधुनिक तकनीक में रोबोट को
ीसीटीवी से जोड़ा जाता है और इसमें किसी
फाईकर्मी को सफाई के लिए सीवर लाइनों
उतारना नहीं पड़ता। यदि कोई डैमेज हो भी
ाए तो तत्काल रोबोट के जरिये उसका पता
ल जाता है। सीसीटीवी से लैस इस पद्धति में
बोट को चलाने के लिए सीवर लाइन के ऊपर

एक व्यक्ति खड़ा होता है जो आवश्यक निर्देश देता रहता है। इस नई तकनीक से लाइव फोटो भी लगातार मिलते हैं जिससे ब्लॉकेज का तत्काल पता चल जाता है।

उधर दिल्ली सरकार ने भी कुछ समय पहले 50 स्पेशल सीवर मशीनें लगाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को खत्म किया जा सके। दिल्ली सरकार ने अपने इस आदेश का उल्लंघन करने पर उम्रकैद की सजा देने तक की बात भी कही है। केरल में सीवर सफाई के दौरान हो रही मौतों की रोकथाम के लिए केरल सरकार भी रोबोट का इस्तेमाल करने लगी है। वहां के युवा इंजीनियरों ने सीवर सफाई के लिए 'बंदीकूट' नामक रोबोट बनाया है। इस रोबोट में हाथ-पांव तथा एक बाल्टी जुड़ी हुई है। इसमें वाईफाई से रोबोट को कंट्रोल किए जाने की भी सुविधा है। रोबोट में ऊर्जा के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सीवर के अंदर मौजूद खतरनाक गैसों में किसी तरह का विस्फोट न हो। जान लेना बेहतर होगा कि पिछले कुछ वर्षों में सर्जरी में भी रोबोट का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। इस पद्धति से शल्य-चिकित्सा काफी सफल हो रही है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

चालबाज अमेरिका से चौकन्ना भारत

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'अमेरिका से भारत की अपेक्षाएं' में जी-20 सम्मेलन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के प्रति संतुलित व्यवहार की नीति को जिस रूप में रेखांकित किया है, वह भारत के लिए जरूरी है। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अमेरिकी मदद की दरकार रखने के बावजूद चौकन्ना भारत अब चालबाज अमेरिका की चालों में फंसने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में जो वैश्विक पहचान बनाई है, उसको कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि भारत अपने हितों के प्रति सचेत रहते हुए अमेरिका के साथ-साथ रूस, चीन, जापान, सऊदी अरब जैसे सक्षम देशों के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखे। विश्व में अपनी हनक बनाए रखने के लिए अमेरिका एशिया महाद्वीप में दबाव बनाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन जब भारत उसके दबाव में नहीं आता है तो यह अमेरिका के लिए कष्टदायी हो जाता है। इस संदर्भ में यह देखने वाली बात है कि जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करते समय रूस, चीन और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्षों की अनदेखी नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी के इस संतुलित व्यवहार से अमेरिका यह सोचने को मजबूर हो गया कि अब बदलते भारत को दबा पाना मुश्किल है। भारत की इस सक्षमता को चीन, अमेरिका, रूस जैसे विश्व के शक्तिशाली देश न केवल समझ चुके हैं, अपितु उसके अनुरूप व्यवहार करने के लिए भी मजबूर हैं। कदाचित यह भारत की सबसे बड़ी सफलता है जो मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने अर्जित की है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मेलबाक्स

कांग्रेस में नेतृत्व संकट

दैनिक जागरण के 29 जून के अंक में संपादकीय आलेख, कांग्रेस का असमंजस, में सही आकलन किया गया है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ भी देते हैं तो पर्दे के पीछे से पार्टी चलाते रहेंगे। कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भी यह जानते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में परिवार से इतर जो भी अध्यक्ष बनेगा वह कठपुतली बन कर रह जाएगा। वैसे कांग्रेस में अभी तो कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा जो पार्टी की नाव को मझधार से निकाल कर आगे ले जा सके। यदि कोई है भी तो वह आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। यदि कोई हिम्मत भी जुटा ले तो कार्यकर्ता का समर्थन कहां से लाएगा? कार्यकर्ता से पार्टी बनती है नेता से नहीं। इसलिए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा। कभी सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ था? यह तो सभी जानते हैं। तब किसी कार्यकर्ता ने केसरी का समर्थन नहीं किया था। यही कारण है कि कांग्रेस के समर्पित नेता असहाय हैं। पार्टी के अध्यक्ष पद पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी व राहुल गांधी तक लंबी परंपरा रही है। सोनिया गांधी ने तो सबसे लंबे समय वर्ष 1998 से लेकर 2017 तक लगातार 19 साल अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। परिवार की सभी पीढ़ियां कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रही हैं, इसलिए कांग्रेस की दयनीय स्थिति के लिए परिवार जवाबदेह है। यदि कांग्रेस परिवार के मोहपाश में बंधी है तो उस पर किसी को एतराज भी क्यों होना चाहिए? यह तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। बेशक इंदिरा गांधी भी उसी परिवार से थीं किंतु यह कटु सत्य है कि उनके बाद कांग्रेस को परिवार से सक्षम नेतृत्व नहीं मिला। यदि कांग्रेस को अपनी स्थिति में सुधार करना है तो उसे किसी कर्मठ नेतृत्व की तलाश करनी ही होगी।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

भाजपा की खूबियों को समझें

विरोधी दलों को समझना होगा कि भाजपा की जीत अंकगणित से ज्यादा मतदाताओं की केमिस्ट्री पर निर्भर है। अपनी विचारधारा पर टिके रहने का धैर्य और रणनीति के साथ लगातार जमीन तैयार करते रहना भाजपा को अन्य दलों से अलग करता है। जनता यदि भाजपा को बेहतर विकल्प के रूप में स्वीकार कर रही है तो उसकी खूबियों को भी समझने की जरूरत है। सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर हमेशा अपना उल्लू सीधा नहीं किया जा सकता। इसलिए ममता का यह कहना कि आज भाजपा हिंदू-मुस्लिमों में भेद पैदा कर रही है और कल बांग्लाभाषियों को और गैर-बांग्लाभाषियों में ऐसा करेगी, मायने नहीं रखता। भाजपा की रणनीति का मुकाबला बेहतर रणनीति से ही संभव है, डर दिखा कर नहीं।

युधिष्ठिर लाल कक्कड, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

चन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई श तिरिक्त।